राज्य का बजट गरीब, आमजन के हितों के विपरीत है: पायलट

जयपुर, 19 फरवरी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा आज विधानसभा में प्रस्तुत बजट को वास्तविकता से परे तथा गरीब व आमजन के हितों के विपरीत बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने बजट भाषण में नयी-नयी घोषणाएं तो कर दीं परन्तु पिछले बजट में की गई घोषणाओं की वर्तमान स्थिति क्या है यह बताने में असफल रही है।

पायलट ने कहा कि आज प्रस्तुत बजट में रोजगार नीति लागू करने तथा युवाओं के लिए सवा लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की गई है परन्तु पिछले वर्ष के एक लाख सरकारी नौकरियां देने के वादे का क्या हुआ, सरकार को आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा रहा है, जो कि चिंताजनक है।

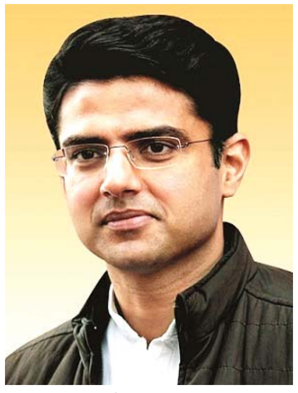

सचिन पायलट

उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ाई गई है परन्तु पिछले एक साल से हजारों करोड़ रूपये की वृहत् परियोजनाओं के टेंडर लम्बित पड़े हैं। इसी प्रकार अमृत 2.0 योजना में शहरों की पेयजल व्यवस्था

- **सचिन पायलट ने कहा कि शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा रहा, जो चिन्ताजनक है।**

के लिए पिछले एक साल में पांच हजार करोड़ रूपये में से एक पैसा भी खर्च नहीं हो पाया और फिर इस बजट में वहीं घोषणा कर दी।

पायलट ने कहा कि जिस ईआरसीपी को लेकर सरकार कह रही है कि 9500 करोड़ रूपये के वर्क ऑर्डर जारी कर दिये गये हैं तथा 12000 करोड़ रूपये के टेंडर आमंत्रित कर लिये हैं, उसके लिए सरकार ने बजट में केवल 200 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है और केन्द्रीय मद में प्रावधान शून्य है।

रेलवे भर्ती के मामले में सीबीआई ने 6 को गिरफ्तार किया

नयी दिल्ली, 19 फरवरी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पश्चिम रेलवे की भर्ती परीक्षा में कथित रिश्वतखोरी का भांडाफोड़ करते हुए छह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जिनमें भारतीय रेल की कार्मिक (आईआरपीएस) सेवा के दो अधिकारियों सहित पांच रेलकर्मी और एक बाहरी व्यक्ति है। जांच एजेंसी ने इस मामले में 11 जगह तलाशी के दौरान 650 ग्राम सोना और पांच लाख रुपये नकद बरामद किए हैं। सीबीआई ने कहा कि उसने पश्चिम रेलवे के सीमित विभागीय (भर्ती) परीक्षा में घूस लेकर अभ्यर्थियों को नौकरी दिलाने के गोरखधंधे का भंडाफोड़ किया है। सीबीआई ने मंगलवार को इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। गिरफ्तार व्यक्तियों में पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल का एक वरिष्ठ अनुमंडलीय कार्मिक अधिकारी, एक अनुमंडलीय कार्मिक अधिकारी (2018 बैच), चर्चगेट (मुंबई) का एक वाणिज्यिक उप-प्रबंधक, एक उप स्टेशन अधीक्षक, साबरमती (अहमदाबाद) अनुमंडलीय रेल अस्पताल के नर्सिंग अधीक्षक और एक बाहरी व्यक्ति शामिल है।

ज्ञानेश कुमार ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाला

नयी दिल्ली, 19 फरवरी। नवनियुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त डॉ. विवेक जोशी ने बुधवार को यहां अपना कार्यभार संभाल लिया।

ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। उन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है जिनका कार्यकाल मंगलवार को सम्पन्न हुआ। ज्ञानेश कुमार का निर्वाचन आयोग के मुख्यालय पर निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने स्वागत

- **साथ ही डॉ. विवेक जोशी ने चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभाला।**

किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने नयी जिम्मेदारी संभालने के बाद एक संक्षिप्त संदेश में नागरिकों, विशेषकर युवा नागरिकों के लिए कहा कि उन्हें मतदान की जिम्मेदारी जरुर निभानी चाहिए। ज्ञानेश कुमार ने कहा, राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम है मतदान, अतः भारत के नागरिक, जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, उन्हें मतदाता जरुर बनना चाहिए और मतदान अवश्य करना चाहिए।

नव नियुक्त चुनाव आयुक्त विवेक जोशी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 1989 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। वह हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव और केन्द्र में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा वित्तीय सेवा विभाग के सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं।

एस.आई. भर्ती पेपर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विचार-विमर्श चल रहा है। ऐसे में राज्य सरकार के स्तर पर कुछ नई जानकारी सामने आ सकती है। ऐसे में आज होने वाली मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी जाए। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से मौजूद अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने भी अपनी सहमति दे दी। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी।

गौरतलब है कि अब तक की सुनवाई में राज्य सरकार ने अदालत को बताया है कि वह दोषी ट्रेनी एसआई को बर्खास्त करना चाहती है, लेकिन कोर्ट की ओर से भर्ती पर यथास्थिति के आदेश होने के चलते उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। वहीं, अदालत भी मौखिक रूप से टिप्पणी कर चुकी है कि यदि सरकार भर्ती पर निर्णय नहीं ले रही तो क्या कोर्ट मामले की जांच सीबीआई को सौंप दे। अदालत ने मंगलवार को हुई सुनवाई में पेपर लीक पर सवाल उठाते हुए कहा था कि आरपीएससी के सदस्य ने भर्ती के करीब 32 दिन पहले ही पेपर लीक कर दिया था। ऐसे में क्या भर्ती की पवित्रता भंग नहीं हुई।

रेखा गुप्ता ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा उनके निर्देश पर चले। महाराष्ट्र में उन्हीं के कहने पर फड़नवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया है।

ट्रम्प व मस्क ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बयूरोक्रैटिक प्रक्रियाओं में ये खो जाते हैं।

ट्रम्प का कहना है कि बाइडन के दिनों से बची हुई ब्योरोक्रेसी उनके खिलाफ काम कर रही है, इसलिए ट्रंप कार्यकारी आदेशों को लागू करने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। मस्क सरकारी आदेश लागू करने की प्रक्रिया पर निगरानी करने के तरीके विकसित कर रहे हैं, ताकि, यह सुनिश्चित किया जा सके कि आदेश सही ढंग से लागू हों। कुछ मीडिया विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों के बीच जल्द ही एक टकराव हो सकता है।

'कोई भी मुझ से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और अमेरिका व उसके व्यापारिक सहयोगियों के बीच में मौजूदा टैरिफ स्ट्रक्चर पर चर्चा की।

ट्रम्प ने कहा, मैंने मोदी से कहा, हम यही करने जा रहे हैं, "रैसिप्रोकल टैरिफ" आप जो भी चार्ज करेंगे, मैं भी करूंगा।

उन्होंने (मोदी ने) कहा, नहीं-नहीं यह ठीक नहीं लगता, मैने कहा, नहीं-नहीं आप जो शुल्क लेंगे मैं भी वहीं लूंगा, हर देश के साथ मैं ऐसा ही कर रहा हूँ।"

उन्होंने कहा, अमेरिका से आयात होने वाले सामान पर विश्व में सबसे ज्यादा टैरिफ भारत में लगाया जाता है, खासकर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, जहाँ ड्यूटी 100 प्रतिशत तक पहुँच जाती है। ट्रम्प के साथ बैठे मस्क ने इसकी पुष्टि की ओर कहा, ऑटो इम्पोर्ट्स पर टैरिफ 100 प्रतिशत है।

उन्होंने कहा, इस तरह के टैरिफ की वजह से भारत में अमेरिकी उत्पाद बेचना असंभव है।

जब तक कि वे वहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट न लगा लें, यह अमेरिकन अर्थव्यवस्था के साथ अन्याय है।

'भारत की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आउट के लिए 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर? यह निश्चित रूप से भारत के चुनावी प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप है। इससे किसे लाभ होता है? निश्चित रूप से सत्तारूढ़ पार्टी को तो नहीं!"

उन्होंने यह भी दावा किया कि अब रद्द की गई योजना पिछली कांग्रेस-नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के समय की ओर इशारा करती है, जिसने भारतीय संस्थाओं में राष्ट्र विरोधी ताकतों की घुसपैठ का रास्ता साफ किया था।

भाजपा व कांग्रेस...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मोदी सरकार के समय यूएस एड को समर्थन देने के लिए आलोचना की और यह पूछा कि भाजपा-नेतृत्त्व वाली एनडीए सरकार को यूएस एड से कितना फंड मिला थे। वहीं, भाजपा ने कांग्रेस को निशाना बनाया। भाजपा के आईटी मीडिया प्रमुख अमित मालवीया ने कहा, 'भारत में वोटर टर्न आउट के लिए 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर। यह निश्चित रूप से भारत की चुनावी प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप है। इससे किसे लाभ होता है? निश्चित रूप से सत्तारूढ़ पार्टी को तो नहीं।' उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 2012 में जब यूपीए सरकार सत्ता में थी, तब मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाय. कुरैशी के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़े एक संगठन इंटरनैशनल फाउण्डेशन ऑफ इलैक्टोरल सिस्टम के साथ एक एमओयू किया था। ओपन सोसायटी को यूएस एड से मदद मिलती है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस से जुड़े भारत विरोधी तत्वों को यूएस एड से वित्त पोषित किया जा रहा था। उन्होंने पूछा, "क्या यूएस एड और जॉर्ज सोरोस ने राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को पैसे दिए थे?" उन्होंने इस मामले की जांच की मांग की।

गहलोत अब डोटासरा...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लिए वे लोग पुल का काम कर सकें। इसके लिए वे टीम सदस्यों का पूरा खयाल रखते हैं।

डोटासरा परिवार काफी धनाढ्य माना जाता है तथा उनकी पांचों उँगलिया घी में बताई जाती हैं।

जब सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत करने के बाद अशोक गहलोत कांग्रेस नेतृत्व के कोपभाजन बन गये थे, उस समय डोटासरा ने उनसे दूरी बनाने की कोशिश की थी। लेकिन दोनों के संबंध इतने गहरे और मजबूत हैं कि दूरी बनाना बहुत मुश्किल था।

पेपर लीक घोटाले में फँसने से डोटासरा को बचाने वाले अशोक गहलोत ही थे, क्योंकि उस समय राजस्थान के शिक्षा मंत्री डोटासरा ही थे।

हैरान करने वाली बात डोटासरा परिवार के तीन सदस्यों के नम्बर ठीक बराबर आये थे, तथा सोशल मीडिया पर यह मामला जमकर ट्रोल हुआ था।

गत वर्ष नवम्बर में, प्रवर्तन निदेशालय ने डोटासरा के दोनों बेटों को पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किया था।

अब राजस्थान और नई दिल्ली के राजनैतिक हल्कों में यह अटकलें जोरों पर हैं कि सचिन पायलट को कांग्रेस अध्यक्ष बनाकर जयपुर भेजा जाये, ताकि वे कांग्रेस संगठन में आमूल चूल परिवर्तन कर के, उसे नये रूप में नये सिरे से खड़ा करें तथा पार्टी को ऐसा रूप दे सकें कि वह अगले विधानसभा चुनावों में भाजपा का मुकाबला कर सके। गहलोत और डोटासरा इन अटकलों से बहुत कष्ट में हैं।

यह था लंच का कारण, यानी मीडिया को अपनी ओर खींचने की कोशिश!

होली के बाद होगी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

याचिकाओं पर 19 फरवरी को प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करेगा। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि समय की कमी के कारण मामले को होली की छुट्टी के बाद सुना जाएगा। फिलहाल कोई तारीख तय नहीं की गई। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ को एक गैर सरकारी संगठन की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने बताया था कि संविधान पीठ के 2023 के फैसले में कहा गया था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियां ऐसा पैनल करेगा, जिसमें भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) भी शामिल होंगे।

यह राजस्थान का पहला ग्रीन बजट है...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करेगी। नगरीय क्षेत्रों में घर-घर नल से जल पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी शुरू किया जाएगा। इसमें 5 हजार 830 करोड़ रूपए की लागत से काम किया जाएगा।

शर्मा ने कहा कि राजस्थान भी अब ग्रीन बजट पेश करने वाले देश के चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है। सस्टेनेबल ग्रीन प्रणाली को प्रोत्साहित करने, क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने, बायोडायवर्सिटी, वाटर हार्वेस्टिंग, ग्रीन एनर्जी, रिसाइक्लिंग आदि को प्रोत्साहित करने के लिए कुल राज्य बजट की 11.34 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसानों की आय बढ़ा कर उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इस क्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रदेश में दी जा रही 8 हजार रूपए की राशि को बढ़ा कर 9 हजार रूपए प्रति वर्ष करने की घोषणा की गई है।

युवाओं के विकास एवं कल्याण के लिए राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाई जाएगी, जिसके अंतर्गत 500 करोड़ रूपए खर्च कर विवेकानंद रोजगार सहायता केन्द्र की स्थापना की जाएगी। चार लाख सरकारी नौकरियों के वादे को पूरा करने की दिशा में आगामी वर्ष में सवा लाख पदों पर सरकारी भर्तियां की जाएंगी। निजी क्षेत्र में भी आगामी वर्ष में डेढ़ लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने पर बजट में विशेष जोर दिया गया है। प्रदेश में जन जन के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के साथ ही, आमजन की निशुल्क जांच एवं दवा हेतु 3 हजार 500 करोड़ रूपये का मा कोष बनाया जायेगा। 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के विशेष केयर पैकेज, किशोरों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के पैकेज, ओरल कैंसर हेतु पैकेज तथा विशेष योग्यजनों हेतु पैकेज इस योजना में जोड़े जाएंगे। ट्रक, बस ड्राइवरों तथा दर्जी, बढ़ई, नाई आदि कारीगरों की आंखों की जांच कर निशुल्क चश्मे उपलब्ध करवाने के लिए मा नेत्र वाउचर योजना लागू की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक साल में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जोड़कर 150 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का भी काम करेगी।

शर्मा ने कहा कि राजस्थान में स्टेट हाइवे, बाईपास, रेलवे ओवर ब्रिज एवं अण्डर ब्रिज आदि के निर्माण, विकास और सुधार के लिए 5 हजार करोड़ रूपये से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। राज्य में 2,750 किमी से अधिक लंबे 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे, जिनकी लागत लगभग 60 हजार करोड़ रूपये होगी। इसके अलावा, 21 हजार किलोमीटर नॉन पैचेबल सड़कों के कार्यो के लिए 6 हजार करोड़ रूपये का बजट रखा गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत और निर्माण के लिए 10-10 करोड़ रूपये दिए जाएंगे, जबकि मरूस्थलीय इलाकों में यह राशि 15-15 करोड़ रूपये होगी। प्रदेश के प्रमुख शहरों में ट्रैफिक के बढ़ते दबाव से राहत दिलाने के लिए 15 शहरों में रिंग रोड के निर्माण का कार्य हाथ में लिया जाएगा।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोरा सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908